web: www.nyaysakshi.com || पृष्ठ-2 में पढ़ें संपादकीय-खेल-व्यापार-धर्म-खाना खजाना-राशिफल || पृष्ठ-3 में पढ़ें छत्तीसगढ़-प्रादेशिक

दैनिक

न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, मंगलवार 17 मार्च 2020 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-02, अंक- 167

देश में जल्द खोले जाएंगे अंबेडकर नवोदय विद्यालय

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने स्कूल जाने वाले एससी के छात्रों को बड़ा तोहफ दिया है। जिसमें जल्द ही सरकार जवाहर नवोदय विद्यालय की तर्ज पर देश में अंबेडकर नवोदय विद्यालय खोलने जा रही है। यह स्कूल भी जवाहर नवोदय की तरह से आवासीय होंगे।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि अंबेडकर नवोदय विद्यालय खोलने के पीछे नरेन्द्र मोदी सरकार का यह मकसद है कि बेहतर संसाधन और अवसर उपलब्ध कराते हुए एससी के मेधावी छात्र-छात्राओं की प्रतिभा को विकसित और प्रोत्साहित किया जाए, जिससे सभी क्षेत्रों में उनका विकास हो सके और उच्च शिक्षा के लिए दूसरे छात्रों के साथ कम्पटीशन कर सकें। वहीं दूसरी ओर रोजगार के अच्छे मौके भी मिल सकें।

खास बात यह है कि यह स्कूल उन इलाकों में खोले जाएंगे जहां एससी की आबादी ज्यादा होगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। मंत्रालय का कहना है कि इस नई

योजना को शुरु करने का प्रस्ताव है। स्कूल कक्षा 6 से 12 तक के होंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार अंबेडकर नवोदय विद्यालय खोलने के पीछे नरेन्द्र मोदी सरकार का यह मकसद है कि बेहतर संसाधन और अवसर उपलब्ध कराते हुए एससी के मेधावी छात्र-छात्राओं की प्रतिभा को विकसित और प्रोत्साहित किया जाए। मंत्रालय के अनुसार हाल ही में केन्द्र सरकार ने घोषणा की थी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को इंटर कॉलेज तक उच्चीकृत किया जाएगा। केंद्र सरकार का कहना है कि पहले चरण में देश के 350 केजीबीवी को कक्षा 9 से 12 तक उच्चीकृत करने की मंजूरी दी गई है।

अभी इन विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है।पहले चरण में 12वीं तक होने वाले 121 केजीबीवी वो हैं जहां 3 किलोमीटर के एरिया में एक भी राजकीय या सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय नहीं है। इन केजीबीवी में कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं संचालित करने के लिए, नया शैक्षिक ब्लॉक तथा 100 छात्राओं के लिए नया छात्रावास बनाया जाएगा। सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत हर स्कूल में नए शैक्षिक ब्लॉक के लिए 1 करोड़ 38 लाख 61 हजार रुपये और छात्रावास निर्माण के लिए 1 करोड़ 77 लाख 16 हजार रुपये मंजूर किए हैं। वहीं पहले चरण में उच्चीकृत होने वाले 229 केजीबीवी ऐसे हैं जहां तीन किलोमीटर की परिधि में राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय है। इन केजीबीवी की छात्राओं को कक्षा 9 से 12 की शिक्षा करीब के माध्यमिक विद्यालय में दी जाएगी, लेकिन छात्रावास की सुविधा मौजूदा केजीबीवी में ही होगी।

महत्वपूर्ण एवं खास

सेना की आर्म्स-एम्यूनेशन लदी ट्रेन हुई बेपटरी

» आर्मी ने कब्जे में लिया पूरा इलाका

रांची (आरएनएस)। लातेहार जिले के टोरी जंक्शन के पूर्वी सिग्नल के पास भारतीय सेना की आर्म्स-एम्यूनेशन लदी एक ट्रेन सोमवार सुबह बेपटरी हो गई। बताया जा रहा है कि सुबह टोरी जंक्शन के पूर्वी सिग्नल के पास रेल लाइन बदलने के चलते यह हादसा हुआ। इसके बाद पूरे इलाके को जवानों ने सुरक्षा के घेरे में ले लिया। मौके पर बड़ी संख्या में आर्मी और पुलिस के जवान मौजूद हैं। जानकारी के अनुसार दक्षिण पूर्व रेल लाइन से पूर्व मध्य रेल लाइन में पटरी बदलने के दौरान ट्रेन बेपटरी हो गई। घटना के बाद ट्रेन पर सवार सेना के जवानों ने पुरे इलाके की घेराबंदी कर ली। उनकी घेराबंदी और रेलवे के वरिय पदाधिकारियों के दिशा निर्देशन में पटरी को दुरुस्त करने का कार्य जारी है।

द्वारका में हथियारबंद अपराधियों ने की कॉन्स्टेबल हत्या

» होमगार्ड का जवान भी हुआ घायल

नईदिल्ली (आरएनएस)। राजधानी दिल्ली के द्वारका सेक्टर-23 में सोमवार की सुबह एक कॉन्स्टेबल की हत्या कर दी गई. कॉन्स्टेबल की हत्या हथियारबंद अपराधियों ने की है. इस दुर्घटना में होमगार्ड का एक जवान भी घायल हो गया है. पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुट गई है। 14 मार्च को भी दिल्ली के रोहिणी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच शनिवार दोपहर मुठभेड़ में एक जवान घायल हो गया था. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया था. वहीं दोनों तरफ से हुई गोलीबारी के दौरान एक पुलिस जवान भी घायल हो गया है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को कुछ शार्प शूटर्स के रोहिणी में होने की सूचना मिली थी. इसके बाद इन बदमाशों को पकड़ने के लिए ट्रेप बनाया गया. जैसे ही बदमाशों की गाड़ी वहां आकर रुकी पुलिस ने उन्हें पकड़ना चाहा लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी।

पत्नी की गोली मारकर हत्या

सतना (आरएनएस)। मध्यप्रदेश के सतना जिले के नागौद थाना क्षेत्र के इंदिरानगर में पारिवारिक विवाद के दौरान एक व्यक्ति ने गोलीमार कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। पुलिस सूत्रों ने आज बताया कि इंदिरानगर निवासी जनार्दन बागरी का कल रात किसी बात को लेकर अपनी पत्नी ममता बागरी (40) से विवाद हो गया। इसी दौरान उसने अपनी लायसेंसी बंदूक से गोली मारकर अपनी ममता की हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज जाँच शुरू कर दी है।

निर्भया के चारों दोषियों के परिजनों ने मांगी इच्छामृत्यु

» राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लिखा पत्र

नईदिल्ली। निर्भया गैंगरेप मामले में अब नया मोड़ आ गया है. फांसी की सजा पाने वाले चारों दोषियों के परिजनों ने अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर इच्छामृत्यु की अनुमति मांगी है. इच्छामृत्यु मांगने वालों में दोषियों के बुजुर्ग माता-पिता, भाई-बहन और उनके बच्चे शामिल हैं. निर्भया के दोषियों के परिजनों ने हिंदी में राष्ट्रपति को लिखे पत्र में कहा है कि हम देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीड़िता के माता-पिता से अनुरोध करते हैं कि वे हमारे अनुरोध को स्वीकार करें और हमें इच्छामृत्यु की अनुमति दें. उन्होंने कहा कि हमें इच्छा मृत्यु देने से भविष्य में होने वाले किसी भी अपराध को रोका जा सकता है. उन्होंने कहा कि अगर हमारे पूरे परिवार को इच्छामृत्यु दी जाती है तो निर्भया जैसी दूसरी घटना को होने से रोका जा सकता है। दोषियों के परिजनों ने कहा है कि ऐसा कोई पाप नहीं है, जिसे माफ नहीं किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि पहले ही देश के महापापियों को माफ किया जाता रहा है. बदले की परिभाषा शक्ति नहीं है. क्षमा करना ही सबसे बड़ी शक्ति का उदाहरण है. गौरतलब है कि निर्भया के सभी दोषियों विनय शर्मा, अक्षय सिंह ठाकुर, पवन गुप्ता और मुकेश को 20 मार्च सुबह साढ़े पांच बजे फांसी दी जानी है।

» स्वीमिंग पूल, जिम, नाइट क्लब, स्पा भी 31 मार्च तक बंद

कोरोना से बचने आपकी सरकार कर रहीं सार्थक प्रयास:केजरीवाल

नईदिल्ली (आरएनएस)। कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने कमर कस ली है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को इसके लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए. उन्होंने कहा कि दिल्ली में स्कूल-कॉलेज को बंद करने के निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

अब जिम, नाइट क्लब, स्पा और स्वीमिंग पूल को भी 31 मार्च तक बंद करने का आदेश दिया गया है. केजरीवाल ने यह भी कहा कि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी में 50 से अधिक लोगों को एक जगह इकट्ठा होने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी. सीएम ने कहा कि भीड़ न जुटाने के आदेश से शादी समारोह जैसे कार्यक्रमों को अलग रखा गया है, लेकिन मेरी लोगों से अपील है कि हो सके तो शादी-विवाह की तारीख को आगे बढ़ा दें. उन्होंने कहा कि वायरस के संक्रमण को देखते हुए दिल्ली में 500 से अधिक बिस्तरों वाले अस्पताल का इंतजाम है. पीड़ितों को अलग रखने के लिए होटलों का भी इंतजाम किया जा रहा है।

केजरीवाल ने कहा कि, मैं अनुरोध और प्रार्थना करता हूं कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए लोग घरों में रहें. उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि, मैं दिल्ली की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपकी सरकार आपको कोरोना वायरस से बचाने के लिए हर प्रयास कर रही है. हमें मिलकर इस से बचना है।

मप्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची भाजपा

नई दिल्ली (आरएनएस)। मध्य प्रदेश में जारी सियासी संकट के बीच सोमवार को विधानसभा में राज्यपाल लालजी टंडन का अभिभाषण हुआ। इसके तुरंत बाद विधानसभा 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में कमलनाथ सरकार को अल्पमत में बताते हुए फ्लोर टेस्ट की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है।

सुप्रीम कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से दायर इस याचिका में अगले 48 घंटों के भीतर मध्य प्रदेश विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की गई है। इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने बताया कि याचिका में कुछ खामियां हैं।

यदि उन खामियों को दूर कर लिया जाता है तो शिवराज सिंह चौहान की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी। इससे पहले पल-पल बदल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच एमपी विधानसभा की कार्यवाही सोमवार को शुरू हुई। राज्यपाल लालजी टंडन ने एक मिनट से भी कम का अभिभाषण देकर इसकी शुरुआत की। उनका भाषण पढ़ा समझ लिया गया। राज्यपाल ने अपने भाषण में कहा कि जिसका जो दायित्व है वो उसका निर्वहन करें। सभी संविधान और परंपरा का पालन करें. मध्य प्रदेश के गौरव की रक्षा हो। इस बीच विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद 26 मार्च तक विधानसभा स्थगित कर दी गई।

शीर्ष 50 ऋण बकाएदार कौन हैं?

» राहुल गांधी का सवाल

नईदिल्ली (आरएनएस)। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को लोकसभा में सरकार से मांग की कि वह शीर्ष 50 ऋण बकाएदारों के नाम उजागर करे। प्रश्न क्रमांक 305 पर सूचीबद्ध था। राहुल गांधी ने सरकार से नाम देने और बकाएदारों से कर्ज वसूलने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी मांगी। राहुल ने लोकसभा में कहा, प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) कहते हैं कि जिन्होंने बैंकों से कर्ज लिया और देश छोड़कर भाग गए हैं, उन्हें वापस लाया जाएगा। मैंने बकाएदारों के नाम जानने चाहे, लेकिन जवाब नहीं मिला। मेरा सवाल है कि शीर्ष 50 ऋण बकाएदार कौन हैं?

मोदी सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र में काफी सुधार किया: ठाकुर

नईदिल्ली (आरएनएस)। बैंकिंग तंत्र की स्थिति को लेकर सोमवार को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार नोंकझोक हुई तथा कांग्रेस सदस्य राहुल गाँधी को इस विषय पर प्रश्न पूछने का पूरा मौका न देने पर कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कषगम् और वामदलों ने सदन में हंगामा तथा बहिर्गमन किया।

गाँधी ने प्रश्नकाल में सरकार से जान-बूझकर बैंकों का कर्ज नहीं चुकाने वालों के बारे में जानकारी माँगी थी। पूरक प्रश्न पूछने का मौका दिये जाने पर उन्होंने कहा कि सरकार ने लिखित उत्तर में शीर्ष 50 ऐसे बकायादारों की सूची नहीं दी है जो उन्होंने माँगी थी। द्रमुक और वामदलों ने भी उनका साथ दिया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है। बैंक विफल हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि

जानबूझकर ऋण न चुकाने वाले बैंकों का पैसा चुराकर भाग रहे हैं।

इस पर वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सदस्य पर खराब दृष्टि से प्रश्न पूछने का आरोप लगाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि बैंकिंग तंत्र की स्थिति के लिए पिछली सरकार जिम्मेदार है जबकि मौजूदा मोदी सरकार ने इसमें काफी सुधार किया है। उन्होंने कहा कि गाँधी जैसे वरिष्ठ सदस्य ऐसे समय में बैंकिंग तंत्र पर सवाल खड़े करना चाहते हैं जब वित्त मंत्री देश को आश्वस्त कर रही हैं कि येस बैंक में लोगों का पूरा पैसा सुरक्षित है।

ठाकुर ने कहा कि यह समझना जरूरी है कि क्या हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। वर्ष 2010-2014 के बीच जो सकल ऋण दिये गये उनमें 0.64 प्रतिशत 'बुरे ऋण' में बदल गये। वित्त वर्ष 2018-19 में यह प्रतिशत घटकर 0.18 प्रतिशत पर आ गया। वर्ष 2019-20 में इसमें और गिरावट आयी है।

कोरोना के खिलाफ लोगों को स्वस्थ रखने में काई कसर नहीं छोड़ी: मोदी

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए समन्वित एवं एकजुट कदम उठाए जा रहे हैं और लोग स्वस्थ रहें, यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पीएम मोदी ने कोरोना वायरस से मुकाबला करने में डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों की कड़ी मेहनत एवं योगदान की सराहना की।

प्रधानमंत्री ने भारत द्वारा कोविड-19 से मुकाबला करने के विभिन्न आयामों को रेखांकित करने वाले विभिन्न लोगों को अपने ट्वीट में टैग भी किया। हैशटैग इंडिया फाइट्स कोरोना से संबंधित ट्वीट में मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने में उठाए गए कदमों को लोगों द्वारा रेखांकित करने से डॉक्टरों, नर्सों, नगरपालिका कर्मियों, हवाई अड्डा कर्मियों एवं अग्रिम मोर्चे पर जुटे लोगों का मनोबल बढ़ता है। एक व्यक्ति ने ट्वीट किया था कि उन्होंने अपनी सभी बैठकें और कारोबारी यात्राएं रद्द कर दीं। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बुद्धिमतापूर्ण निर्णय। गैर जरूरी यात्राओं से बचना सामाजिक कार्यक्रमों को कम से कम करना स्वागत योग्य कदम है।

देश में वरिष्ठ नागरिकों के लिए जल्द आएगी राष्ट्रीय नीति

» नीति के मसौदे को अंतिम रुप देने का काम जारी: गहलोत

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि देश में बुजुर्गों के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने का काम जारी है और सरकार ने सामाजिक समता और समरसता के साथ वंचितों और शोषितों को मुख्यधारा में लाने का काम किया है तथा दिव्यांगों, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य वर्गों के बजट में ऐतिहासिक वृद्धि की है।

लोकसभा में वर्ष 2020-21 के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए गहलोत ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की छात्रवृत्ति के संदर्भ में कुछ सदस्यों के सवालों पर कहा कि केंद्र की तरफसे धन की कमी के कारण कोई छात्रवृत्ति नहीं रुकी है और पंजाब समेत कुछ अन्य प्रदेशों में आंतरिक कारणों से ऐसा हुआ है।

मंत्री के जवाब के बाद सदन ने कुछ विपक्षी सदस्यों के कटौती प्रस्तावों को अस्वीकृत करते हुए ध्वनिमत से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों को पारित कर दिया। गहलोत ने कहा कि देश में बुजुर्गों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने की दिशा में काम जारी है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पहले की नीति में सुधार का प्रयास किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण के लिए एक विधेयक संसद में पेश किया जा चुका है जिसमें उनके लिए डे केयर, वृद्धाश्रम और हर थाने में विशेष प्रकोष्ठ की सुविधा के प्रावधान प्रस्तावित हैं।

उन्होंने कहा कि जो वरिष्ठ जन ओल्ड ऐज होम नहीं जा सकते उन्हें एनजीओ के माध्यम से घर में ही सेवा प्रदान करने प्रावधान भी इसमें है। गौरतलब है कि संसद के शीतकालीन सत्र में 'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019 प्रस्तुत किया गया था जिसे बाद में सामाजिक न्याय और अधिकारिता से संबंधित संसद की स्थायी समिति को अध्ययन के लिए भेजा गया। गहलोत ने कहा कि मोदी सरकार में उनके विभाग ने अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिये हैं और कई कार्यों के लिए अब तक 10 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाये हैं।

इंदौर-किशनगढ़ हवाई सेवा शुरू

नईदिल्ली (आरएनएस)। उड़ान (यूडीएएन-उड़े देश के आम नागरिक) योजना के तहत नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आज इंदौर (मध्य प्रदेश) से किशनगढ़ (अजमेर, राजस्थान) के बीच पहली उड़ान सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जो सप्ताह में तीन दिन चलेगी। विमान सेवा से अब तक नहीं जुड़े क्षेत्रों को जोड़ने के अपने निरंतर प्रयास में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान 3 के लिए बोली प्रक्रिया के दौरान स्टार एयर को इंदौर-किशनगढ़ मार्ग का कार्य सौंपा। इस मार्ग पर विमान सेवा के शुरू होने के साथ उड़ान योजना के तहत 268 हवाई मार्ग पर सेवाएं उपलब्ध हो गई हैं। आरसीएस-यूडीएएन के तहत स्टार एयर पहले से ही बेलगावी से इंदौर के लिए सीधी उड़ानें संचालित कर रही है और अब ‌ऱंगों की भूमि‌ राजस्थान तक उसी मार्ग का विस्तार करेगी। इंदौर और किशनगढ़ के बीच की अनुमानित दूरी लगभग 550 किलोमीटर है और लोग इंदौर से किशनगढ़ सड़क मार्ग से 10 घंटे से अधिक समय में पहुंचते थे। अब इस मार्ग पर विमान सेवा के शुरू होने से लोग एक घंटे में यह यात्रा पूरी कर सकते हैं और प्रसिद्ध नौ ग्रहों के मंदिर, अजमेर शरीफ दरगाह, पुष्कर झील, फूल महल पैलेस, रूपनगढ़ किले इत्यादि का दर्शन कर सकते हैं। किशनगढ़ भारत के मार्बल सिटी के रूप में भी जाना जाता है।

नवनियुक्त सीआईसी बिमल जुल्का ने केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की

नईदिल्ली (आरएनएस)। नवनियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) बिमल जुल्का ने केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। विमल जुल्का सूचना आयोग के लिए नोडल मंत्रालय - कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के प्रभारी भी हैं।

जुल्का 1979 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं। वे केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव के रूप में 2015 में सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें केंद्र में सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। कुछ दिन पहले, सुधीर भार्गव की सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। डॉ. जितेन्द्र सिंह के साथ

अपनी 20 मिनट की मुलाकात के दौरान, मुख्य सूचना आयुक्त ने सूचना आयोग के कामकाज के बारे में जानकारी दी तथा यह बताया कि हाल के वर्षों में सरकार के समर्थन के साथ-साथ आधुनिक तकनीक या पोर्टलों के बढ़ते इस्तेमाल से मामलों के निपटारे की दर में वृद्धि हुई है। जुल्का ने डॉ. जितेंद्र सिंह को जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख के नवसृजित केंद्र शासित प्रदेशों को मुख्य सूचना आयुक्त के दायरे में शामिल करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी जानकारी दी।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने सूचना आयोग के कामकाज में सुधार के लिए मोदी सरकार द्वारा की गई कई ऐतिहासिक पहलों का जिक्र किया और साथ ही साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दाखिल किये गए आवेदनों का शीघ्र निस्तारण के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस सरकार के कार्यकाल में 24 दिन तथा रात में किसी भी हिस्से में एवं देश अथवा विदेश कहीं से भी सूचना का अधिकार की ई-फाइलिंग के लिए 24 घंटे की पोर्टल सेवा शुरू की गई है।